बुधवार , 04 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 69

CITY NEWS MUMBAI

राहुल ने PM मोदी को दी खुली चुनौती

बोले- डरिए मत, मंच पर आमने-सामने बैठिए

राहुल गांधी ने PM मोदी से अमेरिकी डील, अडानी और एपस्टीन मामले समेत कई मुद्दों पर आमने-सामने चर्चा की मांग की। बोले- बहस के लिए मंच और जगह आप चुनिए, जज भी अपनी पसंद का तय कर लीजिए। राहुल गांधी ने PM मोदी को फिर दी खुली बहस की चुनौती, बोले- किसी भी मंच पर जगह चुनिए, डरिए मत अमेरिकी डील, अडानी और एपस्टीन मामले पर आमने-सामने चर्चा की मांग, मोहन भागवत को जज बनाने का भी दिया प्रस्ताव राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह और योगी आदित्यनाथ से PM मोदी को बहस के लिए मनाने की अपील कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी मंच और स्थान का चयन कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच मीडिया और देश के युवाओं की मौजूदगी में आमने-सामने बहस होनी चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी प्रधानमंत्री को इस बहस के लिए मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को देशद्रोही बताते हैं और उस पर विदेशी ताकतों से संबंध रखने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में इन आरोपों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "24 घंटे हो





गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए और डिबेट कीजिए मेरे साथ।" मोहन भागवत को जज बनाने का भी दिया प्रस्ताव राहुल गांधी ने बहस के प्रारूप का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेता एक टेबल पर आमने-सामने बैठेंगे। वहां मीडिया और देश के युवा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिसे चाहें, उसे बहस का जज बना सकते हैं। यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी जज के तौर पर बैठाया जा सकता है। राहुल ने कहा कि बहस के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमेरिकी डील से लेकर अडानी और एपस्टीन तक पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने बहस के संभावित मुद्दों को गिनाते हुए देश के वित्तीय सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अमेरिका के साथ हुई डील, अडानी मामले और एपस्टीन प्रकरण का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिकी डील इतनी जल्दी क्यों हुई, इसके बारे में कैबिनेट को जानकारी क्यों नहीं दी गई और अडानी का केस बंद क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। 45 मानहानि के मामलों का भी किया जिक्र राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ करीब 45 मानहानि के मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूसरे मुद्दों पर मानहानि के मुकदमे करते हैं, लेकिन विदेशी कनेक्शन से जुड़े आरोपों पर ऐसा नहीं किया गया। राहुल ने प्रधानमंत्री से इन सवालों पर भी खुली बहस करने को कहा। इससे पहले राहुल गांधी ने देश के युवाओं से सवाल किया था कि क्या वे नरेंद्र मोदी और उनके बीच खुली बहस देखना चाहते हैं? उन्होंने राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए कहा था कि ये नेता हमेशा प्रधानमंत्री की भलाई के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्हें बहस के लिए मनाएं। राहुल गांधी ने अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं।

गोकुळ दूध संघ में 7.5 लाख दूध उत्पादक किसानों की आवाज दबाने की कोशिश!

सतेज पाटील ने मीडिया से लगाई लोकतंत्र बचाने की गुहार

कोल्हापुर, (सिटी न्यूज़ मुंबई)

महाराष्ट्र विधान परिषद में कांग्रेस के गुटनेता एवं पूर्व मंत्री सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील ने गोकुळ दूध संघ के चुनाव और अध्यक्ष चयन प्रक्रिया को लेकर राज्य के सभी संपादकों एवं पत्रकारों को पत्र लिखकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए सहयोग की अपील की है। सतेज पाटील ने अपने पत्र में कहा है कि कोल्हापुर जिले के करीब साढ़े सात लाख दूध उत्पादक किसान गोकुळ दूध संघ से जुड़े हैं। गोकुळ के चुनाव में 25 में से 23 सीटों पर समर्थित उम्मीदवारों को स्पष्ट बहुमत

मिला था। इसके बावजूद 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चयन के लिए आयोजित बैठक में महायुति के सभी 12 संचालकों के अनुपस्थित रहने के कारण गणपूर्ति नहीं हो सकी और बैठक स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीकी कारणों का सहारा लेकर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है, तो फिर उसके जनादेश का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है? पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि क्या केवल गोकुळ में बहुमत हासिल करने के लिए कानून बदलने या शासन द्वारा नियुक्त संचालकों को मतदान का अधिकार देकर संख्या बल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? उन्होंने आशंका जताई कि आज गोकुळ में जो हो रहा है, वह कल किसी भी सहकारी संस्था में दोहराया जा सकता है। सतेज पाटील ने कहा कि सहकारिता की परंपरा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना जरूरी है। उन्होंने विरोधी संचालकों से भी किसानों के जनादेश का सम्मान करते हुए अगली बैठक में उपस्थित रहने की अपील की है। अंत में उन्होंने महाराष्ट्र के साढ़े सात लाख दूध उत्पादक किसानों की आवाज बनकर मीडिया से इस पूरे मामले को जनता के सामने लाने और लोकतंत्र की रक्षा में सहयोग करने की भावनात्मक अपील की।

महाराष्ट्र सरकार 23 नवंबर को चुकाएगी 6.82% राज्य विकास ऋण 2026 का पैसा; जानिए क्लेम की पूरी प्रक्रिया



महाराष्ट्र सरकार ने 6.82% राज्य विकास ऋण 2026 के मोचन की तारीख का ऐलान कर दिया है। निवेशकों को 23 नवंबर तक मूलधन और ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। महाराष्ट्र के 6.82% सरकारी बॉन्ड का 23 नवंबर को होगा भुगतान निवेशकों को मिलेगा बकाया मूलधन और ब्याज बॉन्ड धारकों को बैंक खाते की जानकारी देने की सलाह महाराष्ट्र सरकार ...शेष 7 पर

महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई, 9 करोड़ के खाद्य उत्पाद जब्त; पतंजलि घी भी शामिल





दिवाली से पहले महाराष्ट्र FDA ने राज्यव्यापी अभियान चलाकर 9 करोड़ के मिलावटी खाद्य उत्पाद जब्त किए। छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि गाय का घी भी किया गया जब्त। महाराष्ट्र FDA ने 9 करोड़ रुपये से अधिक के खाद्य उत्पाद जब्त किए। छत्रपति संभाजीनगर में 2,279 लीटर पतंजलि घी भी जब्त। 19 कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित, 13 FIR दर्ज और 16 गिरफ्तार। दिवाली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यव्यापी ...शेष 7 पर

दीया मिर्जा विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

BMC को वीडियो फिर से अपलोड करने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो को हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालन ने वीडियो को फिर से अपलोड करने के निर्देश दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के एक वीडियो को हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को निर्देश दिया है कि वह हटाए गए वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिर से अपलोड करे। इस वीडियो में दीया मिर्जा लोगों से मुंबई की सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील कर रही थीं। यह वीडियो सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर लगी कोर्ट की रोक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था। क्या





है दीया मिर्जा वीडियो विवाद? यह मामला मुंबई की सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील से जुड़ा हुआ है। अदालत के पूर्व आदेशों के अनुसार, मुंबई की सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसी कानूनी रोक और वायु प्रदूषण के प्रति आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से BMC ने एक विशेष अभियान शुरू किया था। इस सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए प्रशासन ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा को जोड़ा था। दीया मिर्जा ने एक वीडियो संदेश के जरिए नागरिकों से अपील की थी कि वे सड़कों पर पटाखे फोड़कर वायु प्रदूषण न बढ़ाएं और अदालती दिशा-निर्देशों का पालन करें। भाजपा नेताओं की आपत्तियों के बाद BMC ने हटाया वीडियो हालांकि, वीडियो जारी होते ही इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इस वीडियो संदेश पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। राजनीतिक नेताओं की इन आपत्तियों और तीखी टिप्पणियों के तुरंत बाद BMC ने बिना कोई ठोस कारण बताए अपने आधिकारिक ...शेष 7 पर

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज, पप्पू यादव की निकली भड़ास; कहा- माफ नहीं करेंगे

28 अक्टूबर को कथावाचन के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने श्रीकृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जिसके बाद अब पप्पू यादन ने उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया है। पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई पप्पू यादव बोले- धीरेंद्र शास्त्री को माफ नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के करैरा में श्रीकृष्ण के ऊपर की थी विवादित टिप्पणी धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पप्पू यादव ने FIR दर्ज करवाई है। बता दें कि ये पूरा मामला 28 अक्टूबर का है जब धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के करैरा में एक कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम के स्वरूप व विशेषताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। जिसके बात राजनीतिक चहलकदमी तेज हो गई। धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज पप्पू यादव ने मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया 'X' पर कहा कि भगवान श्रीकृष्ण जी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे! सत्ता संरक्षित टुटपुंजिये फरेबी कथावाचक के खिलाफ



आज मैं मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूं! कृष्ण कन्हैया जी को अपमानित कर ये मूर्ख बेईमान अब माफी मांगने की नौटंकी कर रहा है। इसे छोड़ेंगे नहीं, सजा दिलाकर ही मानेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने श्रीकृष्ण पर की थी विवादित टिप्पणी 28 अक्टूबर को कथावाचन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप है। जिसके बाद दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में सांसद पप्पू यादव और यादव समाज द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। धीरेंद्र शास्त्री ने कथावाचन के दौरान कहा था कि 'तुम अपने ठाकुर जी की एक भी फोटो देख लो, बैठे हैं ऐसे तो ऐसे...कहीं ऐसे। अगर तुम्हारे वाले (श्री कृष्ण) खड़े भी होते हैं तो तीन जगहों से टेढ़े। पांव के ऊपर पांव, कमर कहीं लचकाएं, खोपड़िया ऐसी करें, ऐसी खोपड़िया करें, फिर बंसी बजाएं ऐसे टेढ़े करके। इसके बाद उन्होंने भगवान राम की तुलना करते हुए कहा कि हमारे वाले तो खड़े भी होते हैं एकदम सीधे। हमारे वाले का नाम भी सीधा। हमारे वाले का चलना भी सीधा, हमारे वाले दिखते भी सीधे। तुम्हारे वालों का नाम भी टेढ़ा, चलते भी टेढ़े, खड़े भी टेढ़े होते हैं।' धीरेंद्र शास्त्री इस बयान को लेकर माफी भी मांग चुके पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी भी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम एक ही हैं। दोनों में अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या बंटवारा करना नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के मन को ठेस पहुंची है तो वह क्षमा मांगते हैं।

हेमंत का राहुल गांधी पर वार: बोले- खड़गे के बरामदे में ही पीएम बन सकते हैं राहुल, मॉक पार्लियामेंट पर कसा तंज!

असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा का राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल कभी लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मॉक पार्लियामेंट को लेकर हेमंत ने दिया बड़ा बयान असम के सीएम हेमंत विस्वा सरमा ने राहुल पर किया कटाक्ष भाजपा ने विपक्ष के मॉक पार्लियामेंट की आलोचना की बीते दिनों इंडिया गठबंधन के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया आयोजित नकली संसद (मॉक पार्लियामेंट) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता केवल खड़गे के बरामदे में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विपक्ष की इस



प्रतीकात्मक कार्यवाही पर कटाक्ष करते हुए सरमा ने कहा कि राहुल गांधी कभी लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और नरेंद्र मोदी ही इस पद पर बने रहेंगे। शर्मा ने आगे कहा, राहुल गांधी केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के बरामदे में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वह लोकसभा में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। INDIA गठबंधन का मॉक पार्लियामेंट मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी तब आई, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन ने 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में खड़गे के आवास पर एक नकली संसदीय कार्यवाही आयोजित की। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक तरह की सार्वजनिक महाभियोग प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया। इस कार्यवाही की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने की, जबकि खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। राहुल गांधी ने समापन भाषण दिया। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग पर चुनावी निष्पक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर चिंता जताई। भाजपा ने की आलोचना भाजपा ने विपक्ष की इस पहल की आलोचना की है। उन्होंने इसके राजनीतिक उद्देश्यों पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह अपनी चुनावी हार को छिपाने के लिए 'SIR' के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है।

दुनिया के किन 10 देशों में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा ? भारत दूसरे नंबर पर



दुनिया के किस देश में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है? क्या भारत पहले नंबर पर है? क्या भारत के अलावा कोई और देश भी है जहां हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है? दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले टॉप-10 देशों की सूची। नेपाल, भारत और मॉरीशस में हिंदू आबादी का प्रतिशत। टॉप-10 में शामिल एकमात्र मुस्लिम बहुल देश कतर की स्थिति। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप से हुई और समय के साथ यह दुनिया के कई देशों तक पहुंचा। ऐसे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि दुनिया के किन देशों में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा हैं? और यदि है तो उस देश का कितना प्रतिशत? नेपाल में सबसे ज्यादा 80.6 फीसदी हिंदू आबादी डेटापांडास साइट के मुताबिक, नेपाल की कुल आबादी में 80.6 फीसदी हिंदू हैं। इस तरह नेपाल दुनिया का वह देश है, जहां आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं।

BSF जवान पर हमले के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन! अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी, जगह-जगह रो रही छापेमारी



त्रिपुरा पुलिस ने बोक्सानगर के अशाबारी इलाके में बीएसएफ जवान पर हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। अब तक आठ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। BSF जवान पर हमले को लेकर त्रिपुरा पुलिस का एक्शन पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है जवान पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद गुस्सा हुआ था त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के बोक्सानगर में अशाबारी इलाके में BSF जवानों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। त्रिपुरा पुलिस ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें खोजने की कोशिशें जारी हैं। यह हमला तब हुआ जब BSF के जवान भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध तस्करी गतिविधियों के खिलाफ एक अभियान चला रहे थे। हमला और तोड़फोड़ की घटना हुई थी 2 नवंबर को भीड़ ने BSF जवानों पर हमला किया, उनके वाहन में तोड़फोड़ की और उनके हथियार छीनने की कोशिश की।

प्रदर्शन के नाम पर कब्जा नहीं कर सकते...जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- तय हो समय और जगह

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोई भी संगठन अनिश्चितकाल तक सार्वजनिक जगहों पर कब्जा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकते कोर्ट ने प्रोटेस्ट के लिए निर्धारित जगह और समय की जरूरत बताई जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शनों पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सेंट्रल दिल्ली प्रोटेस्ट मामले में सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चित काल तक किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकता है। ऐसी गतिविधि के लिए तय जगहों का भी एक तय समय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पिछले महीने सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए बड़े प्रदर्शन और हाल ही में रामलीला मैदान



में विपक्षी पार्टियों और दूसरों द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन पर सुनवाई के दौरान कही। सरकार ने जंतर-मंतर से तय धरना स्थल की सूची से हटा दिया है और रामलीला मैदान समेत तीन दूसरी जगहों का ऐलान किया। हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो कोई भी प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे अपने कामों के नतीजे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप हमेशा के लिए किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। दूसरे प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान या वकील कहां जाएंगे? बेंच ने आगे कहा कि, हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने व्यापारी संगठन की उस याचिका पर केंद्र और दूसरों से जवाब मांगा, जिसमें त्योहारों के सीजन के दौरान प्रदर्शन रोकने की मांग की गई थी। सीजेपी ने जंतर-मंतर पर कब्जा किया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन की अनुमति केवल एक दिन के लिए दी गई थी, लेकिन प्रदर्शन करने वालों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया और संसद तक मार्च भी किया। उन्होंने कहा, संसद केवल एक और राजनीतिक भवन नहीं है। आप संसद तक मार्च नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट तक मार्च नहीं कर सकते। बेंच कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें व्यापारियों की तरफ से दाखिल की गई याचिका भी शामिल थी, जिसमें कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट बंद करने के मुद्दे शामिल थे।

पुलिस स्टेशन गए बिना ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करें? जानें Step By Step पूरा प्रोसेस

अब पुलिस स्टेशन जाए बिना घर बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। जानिए डिजिटल पुलिस पोर्टल और UPCOP ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करने का पूरा तरीका और जरूरी प्रक्रिया। भारत में ऑनलाइन FIR और पुलिस शिकायत दर्ज कराने की सुविधा। डिजिटल पुलिस पोर्टल से राज्यों के पुलिस विभाग की वेबसाइट तक पहुंचने का तरीका। UPCOP ऐप पर अकाउंट बनाकर ऑनलाइन FIR दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया। क्या बिना पुलिस स्टेशन गए FIR दर्ज हो सकती है? और यदि हां, तो कैसे? यदि ऐसे सवाल आपके मन में हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है। मान लीजिए आपके साथ कोई ऑनलाइन ठगी हो गई है और आप समय की कमी या फिर किसी और कारणवश पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। ऐसे में बिना पुलिस स्टेशन गए आप मात्र कुछ ही मिनटों में घर से, ऑफिस में बैठे या यात्रा करते समय भी FIR दर्ज करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप कैसे ऑनलाइन अपनी शिकायत या फिर FIR दर्ज करा सकते हैं? भारत के किन राज्यों में ऑनलाइन FIR की सुविधा? भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन FIR या शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट डिजिटल पुलिस



पर विजिट करें। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आधिकारिक साइट है। यहां पर आप किसी भी राज्य के पुलिस विभाग की वेबसाइट पर सीधे विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर किसी एक राज्य का चयन करना होगा। उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस राजस्थान पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किसी गांव के रहने वाले हैं। तो जानिए सबसे पहले आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर से UPCOP ऐप डाउनलोड करें सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का UPCOP ऐप डाउनलोड करना है। यह ऐप यूपी पुलिस का आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है। UPCOP का पूरा नाम- उत्तर प्रदेश नागरिक सेवा ऐप है। UPCOP को साइन अप कैसे करें? UPCOP ऐप को ओपन करें। नीचे आपको SIGN UP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद Create Account पर अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें। इसके बाद अपना पासवर्ड बनाएं और ओके करें। अब आपका UPCOP पर अकाउंट बन गया है। UPCOP को लॉगिन कैसे करें? अकाउंट बनने के बाद फिर से लॉगिन पेज पर जाएं। जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आप ओटीपी के माध्यम से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको 6 अलग-अलग सेवाएं डिस्प्ले पर शो होंगी। सबसे ऊपर FIR का ऑप्शन शो होगा। UPCOP ऐप के FIR ऑप्शन में क्या जानकारी भरें? FIR ऑप्शन ओपन करने पर आपको यहां अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे- अपना नाम, पिता का नाम, अपनी उम्र, पूरा पता, जिला और पुलिस स्टेशन का नाम।

2014 से पहले सिर्फ 5 शहरों में थी मेट्रो, पुणे पिंक लाइन के उद्घाटन समारोह से PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला

पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो पिंक लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो की नई लाइन का वर्चुअली लोकार्पण किया। पुणे में हिंजवड़ी से शिवाजी नगर के बीच चलेंगी नई मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर सीधा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पुणे मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों की खुशियां तब और बढ़ जाती हैं, जब जीवन में कोई नई सुविधा जुड़ती है। आज पुणे के लोगों के लिए ऐसा ही एक सुखद अवसर है। मुझे बेहद खुशी है कि आज पुणे मेट्रो की एक और नई लाइन का लोकार्पण हुआ है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिलेगा। आईटी हब को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी पीएम मोदी ने



कहा कि 10 वर्ष पहले मुझे पुणे में पहले चरण के काम के शिलान्यास का अवसर मिला था। अब हिंजवड़ी से शिवाजी नगर के बीच मेट्रो शुरू होने से पुणे के एक बड़े आईटी हब को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। आज जिस नई लाइन पर काम शुरू हुआ है, उससे पुणे के पुराने और नए इलाकों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। मैं पुणे और महाराष्ट्र के सभी लोगों को बधाई देता हूं। पुणे शहर हमेशा से ऐसे विचारों का केंद्र रहा है, जिनसे राष्ट्र और समाज को नई दिशा मिली है। आज पुणे विकसित भारत की नई उर्जा को भी दिशा दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टार्टअप्स, इनोवेशन से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग तक पुणे देश के युवाओं के लिए सपनों और संकल्प का स्थान है। ऐसे में मजबूत होती यहां की मेट्रो कनेक्टिविटी पुणे शहर के विकास को नई गति देने जा रही है। पुणे मेट्रो का लोकार्पण और इसका विस्तार यह दिखाता है कि विकसित भारत के लिए हम कैसे शहरों का निर्माण कर रहे हैं। ...तो पुणे में मेट्रो को पहुंचने में कई दशक और लग जाते इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साल 2014 तक देश में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो चल रही थी। अगर वही पुरानी सोच चलती, पुरानी सरकार रहती, पुरानी कार्य संस्कृति रहती तो पुणे में मेट्रो को पहुंचने में कई दशक और लग जाते। 12 वर्षों में मेट्रो ट्रांसपोर्ट का कायाकल्प उन्होंने आगे कहा कि 2014 में जब देश ने एनडीए को सेवा का मौका दिया तो हम एक संकल्प लेकर चले। यह संकल्प था कि शहर में रहने वाले मिडिल क्लास की ईज ऑफ लीविंग, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नतीजा आज हम देख रहे हैं। बीते 12 वर्षों में देश में मेट्रो ट्रांसपोर्ट का कायाकल्प हो चुका है। हर रोज एक करोड़ यात्री मेट्रो से यात्रा करते हैं पीएम ने बताया कि अब हर रोज मेट्रो में एक करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं।

क्या सच में PM मोदी दे रहे सभी को 8,000 रुपए का दिवाली बोनस, जानें इसके पीछे का खेला



दिवाली में हर कोई बोनस पाकर खुश हो जाता है। ऐसे में WhatsApp पर हो रहे इस स्कैम का गलती से भी शिकार मत हो जाइएगा। PM मोदी नहीं दे रहे हैं WhatsApp पर Diwali Bonus भूलकर भी ठगी का शिकार न बनें। अपना OTP, UPI PIN या बैंक संबंधित जानकारी साझा न करें। दिवाली पर हर कर्मचारी को बोनस दिया जाता है। ऐसे में लोगों के साथ WhatsApp Scam करना आसान हो गया है। इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ स्कैमर WhatsApp पर फ्रॉड मैसेज भेजते हैं। आपको मैसेज में कहा जाता है कि पीएम मोदी हर भारतीय को दिवाली के मौके पर 8,000 रुपए का बोनस दे रहे हैं। इस बीच भूलकर भी भेजे गए लिंक पर क्लीक मत कर दीजिएगा वरना आपका खाता सफाचट हो जाएगा। पीएम मोदी के नाम पर Diwali Scam दिवाली पर 8,000 रुपए का दावा करने वाला मैसेज WhatsApp पर वायरल हो रहा है। अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने इसे फेक बताया है।

दिल्ली में पुलिस बनाम पुलिस, सड़क पर उतरे 150 पुलिसकर्मी, जानिए क्या हैं पांच मांगें और क्यों भड़का विवाद



दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर करीब 150 पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस कमीश्नर ने मिलकर अपनी पांच मांगे रखी। 2019 के बाद पुलिसकर्मियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के करीब 150 जवानों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर अनुराग कुमार को पांच मांगों का ज्ञापन सौंपा साल 2019 के बाद दिल्ली पुलिसकर्मियों का मुख्यालय के बाहर यह बड़ा प्रदर्शन है दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार मामला कुछ अलग है क्योंकि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पुलिस के जवान ही पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। सोमवार को करीब 150 पुलिसकर्मी मुख्यालय के बाहर जमा हुए।

दिल्ली की जहरीली हवा के बीच DMRC का बड़ा ऐलान, अब मेट्रो लगाएगी 20 अतिरिक्त फेरे; राजधानी में GRAP-2 लागू

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-2 लागू हो गया है। DMRC अब सप्ताह के दिनों में 20 अतिरिक्त मेट्रो फेरे लगाएगी, ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल घटाया जा सके। दिल्ली में AQI 324 पहुंचने के बाद GRAP का दूसरा चरण लागू किया गया DMRC सप्ताह के दिनों में 20 अतिरिक्त मेट्रो फेरे लगाएगी ट्रैफिक पुलिस वाहनों के PUC प्रमाणपत्रों की जांच और सख्त करेगी दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा ऐलान किया है। DMRC ने सोमवार को घोषणा की कि नेशनल कैपिटल रीजन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-2 लागू होने के बाद अब मेट्रो सप्ताह के दिनों में 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए



प्रोत्साहित करना है। DMRC ने कहा कि अतिरिक्त मेट्रो सेवाओं से उसके नेटवर्क पर कुल 40 फेरे बढ़ जाएंगे। इससे यात्रियों को सफर के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और निजी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में GRAP का दूसरा चरण लागू दिल्ली की हवा इस सीजन में पहली बार 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सोमवार को पूरे राजधानी क्षेत्र में GRAP के दूसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। 2 नवंबर को शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 दर्ज किया गया। CAQM के मुताबिक, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रह सकती है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत है। ट्रैफिक और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती प्रदूषण कम करने के लिए व्यस्त सड़कों और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्रों की जांच तेज की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने और स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों से जुड़े नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। इन उपायों का मकसद सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना है। तीन दिनों में तेजी से बिगड़ी दिल्ली की हवा CAQM की GRAP सब-कमेटी ने सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की।

सम्पादकीय

आयोग के हलफनामे ने आरोपों का पर्दाफाश कर दिया।

तीनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे से वह खबर झूठी साबित हो गई है जिसके आधार पर छात्र प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। इस हलफनामे के बाद राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। मतदाता सूची गहन समीक्षा (एसआईआर) के विरोध में दिल्ली में रैलियां करके ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभियान के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा आदेश आने पर राहुल गांधी असहाय हो गए। इसी बेबसी के चलते उन्हें 'एसआईआर' के खिलाफ याचिका दायर करनी पड़ी। रैलियों से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाए। किसी जनसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसी का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेबुनियाद आरोप लगाए। देश में खुद को एकमात्र आक्रामक नेता साबित करने की जिद में राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती कर दी। यह गलती थी सर्वोच्च न्यायालय में रैलियां करना। राजनीतिक रैलियां संसद भवन या अन्य सरकारी कार्यालयों में होती हैं। अदालत रैलियों और विरोध प्रदर्शनों जैसी राजनीतिक गतिविधियों से दूर है। अदालत में अपनी शिकायतें और आपत्तियां याचिकाओं के माध्यम से रखी जाती हैं। आपकी शिकायत की वैधता अदालत में दस्तावेजों या अन्य सबूतों के साथ साबित करनी होगी। यहां तक कि एक पार्षद या वार्ड स्तर के कार्यकर्ता को भी यह बुनियादी जानकारी होती है कि अदालत रैली करने की जगह नहीं है। चार बार सांसद चुने जाने के बावजूद राहुल गांधी को यह बुनियादी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी की आक्रामकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के युवराज को फटकार लगाई। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के बेतुके आरोप लगाए। चुनाव आयोग के 'SIR' अभियान के खिलाफ पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी थी। इस याचिका में चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान वैध था और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 'SIR' के खिलाफ यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 'SIR' के खिलाफ लगे आरोप बंद हो गए। हालांकि, एक प्रमुख समाचार पत्र ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि 'एसआईआर' के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथी चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद था। चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी और डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने 'एसआईआर' से संबंधित कुछ मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष कई बार अपना अलग रुख व्यक्त किया था। हालांकि, अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब यह खबर प्रकाशित हुई, तो विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खबर के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की होड़ मच गई। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहकर राहुल गांधी और विपक्षी दल खुद अपने ही जाल में फंस गए। मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगकर और सुप्रीम कोर्ट जाकर राहुल गांधी ने कुछ समय के लिए सुर्खियां बटोरीं, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ लगे आरोपों को अदालत में साबित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। ऐसा कोई नियम या संकेत नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश किसी राजनीतिक मांग के लिए संबंधित पक्षों से मिलें। इसलिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप जो भी कहना चाहते हैं, याचिका के माध्यम से कहें, तो राहुल गांधी के पास 'एसआईआर' के खिलाफ याचिका दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इससे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या 'एसआईआर' में अनियमितताओं का कोई सबूत है। इस पर राहुल गांधी ने विपरीत रुख अपनाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह साबित करना चाहिए कि 'एसआईआर' में कोई गड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी की याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तदनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में 'एसआईआर' के संबंध में जारी किए गए आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त डॉ. जोशी और डॉ. संधि की सहमति से जारी किए गए थे। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि 'एसआईआर' से संबंधित निर्णय चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। इसके साथ ही, तीनों चुनाव आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि चुनाव आयोग के प्रपत्र संख्या 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चुनाव आयुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे ने विपक्ष के आरोपों की पोल खोल दी है। राहुल गांधी और कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों ने एक अखबार की खबर के आधार पर दिल्ली की सड़कों पर तमाशा किया था। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चढ़कर सुर्खियां बटोरी थीं। तीनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे से वह खबर झूठी साबित हो गई है जिसके आधार पर छात्र प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी।

मुनाफाखोरी की गिरफ्त में मरीज

भारत ने पिछले तीन दशकों में चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। दुनिया की हर पांच में से एक जेनेरिक दवा भारत में बनती है। इसलिए भारत को 'विश्व फार्मेसी' कहा जाता है। भारत ग्लोबल साउथ सहित कई देशों के लिए चिकित्सा पर्यटन का विश्वसनीय केंद्र भी है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक चिंताजनक तस्वीर भी है, जो हमारे मेडिकल स्टोर पर रोज दिखाई देती है। यह तस्वीर दवाओं की ऊंची कीमतों और उससे भी गंभीर नकली तथा घटिया दवाओं के बढ़ते कारोबार की है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक संकट भी है, जहां मुनाफे की लालसा जीवन के मूल्य पर भारी पड़ रही है। ध्यान देने योग्य है कि दवाओं की कीमत और गुणवत्ता केवल उनके निर्माण की लागत और वैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि निर्माता से मरीज तक पहुंचने वाली आपूर्ति व्यवस्था से भी प्रभावित होती है। इसी क्रम में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एनपीपीए) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कैंसर की 137 गैर-अनुसूचित दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है। ये दवाएं अब तक मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं थीं। एनपीपीए की जांच में सामने आया कि इन दवाओं पर 700 प्रतिशत तक ट्रेड मार्जिन वसूला जा रहा था। उदाहरण के लिए, कंपनी जिस दवा को 10 हजार रुपये में स्टाकिस्ट को बेचती थी, उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 50 हजार रुपये तय किया जाता था। यानी बिचौलियों, वितरकों, अस्पतालों की फार्मेसी और करों के नाम पर कीमत में 40 हजार रुपये का अंतर था। सरकार ने ट्रेड मार्जिन को एमआरपी के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इससे एमआरपी में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है। इसी व्यवस्था के तहत एनपीपीए ने 2019 में 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित किया था। तब उनकी कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। मार्जिन सीमित करने का अर्थ कंपनियों की कमाई घटाना नहीं है। निर्माता को उसका निर्धारित मूल्य मिलता रहेगा, जबकि बिचौलियों का असामान्य मुनाफा घटेगा। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि मूल्य नियंत्रण से नवाचार प्रभावित होगा। यहां एक सवाल यह है कि क्या केवल ट्रेड मार्जिन सीमित करने से कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज सस्ता हो जाएगा? ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित करना और निर्माता द्वारा तय की गई कीमत को नियंत्रित करना दो अलग-अलग पहलू हैं। यदि निर्माता शुरुआती कीमत ही बहुत अधिक तय करता है, तो 30 प्रतिशत मार्जिन की सीमा के बाद भी दवा महंगी रहेगी। इसके अलावा कंपनियां 'आर्टिफिशियल डिस्काउंट' का तरीका भी अपनाती हैं। वे चुनिंदा बड़े कारपोरेट अस्पतालों को कुछ यूनिट पर भारी छूट देकर कम बाजार मूल्य का आभास देती हैं, जबकि बाकी दवाएं ऊंची कीमत पर ही बिकती हैं। इससे नियामक के लिए दवा का वास्तविक बाजार मूल्य तय करना कठिन हो जाता है। इसलिए ट्रेड मार्जिन नियंत्रण के साथ कीमतों की सख्त निगरानी और बिक्री तथा छूट की पारदर्शी रिपोर्टिंग भी जरूरी है। यह व्यवस्था सभी दवाओं पर लागू होनी चाहिए। नकली और घटिया दवाओं की समस्या महंगी दवाओं से भी जुड़ी है। जब दवाएं बहुत महंगी हो जाती हैं तो नकली दवाओं के लिए बाजार तैयार हो जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार, बाजार में तीन से पांच प्रतिशत दवाएं मानक गुणवत्ता से कम या नकली हैं। सरकार को कानून और तकनीक के जरिये नियमन एवं निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। एनपीपीए को स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जो चार पहलुओं पर नजर रखे-मरीज का कुल बिल, दवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की बिलिंग और इलाज तक पहुंच। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कीमतें घटने के बाद संबंधित दवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में उपलब्ध रहें, क्योंकि कंपनियां अक्सर कम मुनाफे वाली पुरानी दवाओं का उत्पादन बंद कर देती हैं। अब 300 से अधिक दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य है, जिसे स्कैन करके असली और नकली दवा की पहचान की जा सकती है। इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन कर नकली दवा बनाने को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रविधान है। पिछले दो वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का पालन नहीं करने वालीं 150 से अधिक कंपनियों के लाइसेंस रद किए गए हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का विस्तार हो। आज 14 हजार से अधिक केंद्रों पर दो हजार से अधिक दवाएं 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। डाक्टरों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे पर्चे पर किसी खास कंपनी की दवाएं अस्पष्ट लिखने के बजाय स्पष्ट रूप से जेनेरिक दवाओं के नाम लिखें। आज चिकित्सा तंत्र मुनाफाखोरी की गिरफ्त में है। इसका एक कारण चिकित्सा शिक्षा का महंगा और सीमित होना भी है। सरकार को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सर्वसुलभ सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। साथ ही निजी चिकित्सा शिक्षा की फीस को नियंत्रित करने के कदम भी उठाने चाहिए।

4 नवंबर जन्मदिवस पर विशेष।

वासुदेव बलवंत फड़के : देश का पहला क्रांतिकारी, जिससे थर-थर कांपते थे अंग्रेज़।

अगर बात करे भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति और उन क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से देश को आजादी मिली तो इतिहास की रेत में शायद हज़ारों नाम दबे मिले। पर हम सिर्फ कुछ नामों से ही रु-ब-रु हुए हैं। वैसे तो भारत माँ के इन सभी सपूतों के बारे में जानकारी सहेजने की कोशिश जारी है ताकि आने वाली हर पीढ़ी इनके बलिदान को जान-समझ सके। ऐसा ही एक महान क्रांतिकारी और भारत माँ का सच्चा बेटा था वासुदेव बलवंत फड़के! फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रान्तिकारी थे। उनका जन्म 4 नवंबर, 1845 को महाराष्ट्र के रायगड जिले के शिरढोणे गांव में हुआ था। साल 1857 की क्रांति की विफलता के बाद एक बार फिर भारतीयों में संघर्ष की चिंगारी फड़के ने ही जलाई थी। वासुदेव बलवन्त फड़के बचपन से ही बड़े तेजस्वी और बहादुर बालक थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक़ था। कल्याण और पुणे में उनकी शिक्षा पूरी हुई। फड़के के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर दस रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर लें। लेकिन फड़के ने यह बात नहीं मानी और मुम्बई आ गए। उन्होंने 15 साल पुणे के मिलिट्री एकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। इस सबके दौरान फड़के लगातार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के सम्पर्क में रहे। उन पर खास प्रभाव महादेव गोविन्द रानाडे का था। फड़के के में पहले ही ब्रिटिश राज के खिलाफ बग़ावत के बीज पड़ चुके थे। ऐसे में एक और घटना हुई और इस घटना ने फड़के के पुरे जीवन को ही बदल दिया। साल 1871 में, एक शाम उनकी माँ की तबियत खराब होने का तार उनको मिला। इसमें लिखा था कि 'वासु' (वासुदेव बलवन्त फड़के) तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद न हो सकेंगे। इस तार को पढ़कर वे विचलित हो गये और अपने अंग्रेज़ अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना-पत्र देने के लिए गए। किन्तु अंग्रेज़ तो भारतीयों कोअपमानित करने के लिए तैयार रहते थे। उस अंग्रेज़ अधिकारी ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, लेकिन फड़के दूसरे दिन अपने गांव चले आए। पर गांव जाकर देखा कि माँ तो अपने प्यारे वासु को देखे बिना ही इस दुनिया को छोड़ गयीं। इस बात का उनके मन पर बहुत आघात हुआ और उन्होंने तभी वह अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी। देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें देशी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू की। साल 1879 में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम-घूमकर नवयुवकों से विचार-विमर्श किया, और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोळी, भील तथा धांगड जातियों को एकत्र कर उन्होने 'रामोशी' नाम का क्रान्तिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होने धनी अंग्रेज साहुकारों को लूटा। महाराष्ट्र के सात ज़िलों में वासुदेव फड़के की सेना का ज़बर्दस्त प्रभाव फैल चुका था। जिससे अंग्रेज़ अफ़सर डर गए थे। इस कारण एक दिन बातचीत करने के लिए वे विश्राम बाग़ में इकट्ठा हुए। वहाँ पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई, 1879 को रात 12 बजे वासुदेव बलवन्त फड़के अपने साथियों सहित वहाँ आ गए। अंग्रेज़ अफ़सरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें ज़िन्दा या मुर्दा पकड़ने पर पचास हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया। किन्तु दूसरे ही दिन मुम्बई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज़ अफ़सर 'रिचर्ड' का सिर काटकर लाएगा, उसे 75 हज़ार रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज़ अफ़सर इससे और भी बौखला गए। फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फड़के की सेना का गोला-बारूद धीरे-धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में उन्होंने कुछ समय शांत रहने में ही समझदारी मानी और वे पुणे के पास के आदिवासी इलाकों में छिप गये। 20 जुलाई, 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। पर किसी ने उनके यहाँ होने की खबर ब्रिटिश अफसर को दे दी। और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गयी। लेकिन एक बहुत ही विख्यात वकील महादेव आप्टे ने उनकी पैरवी की। जिसके बाद उनकी मौत की सजा को कालापानी की सजा में बदल दिया गया और उन्हें अंडमान की जेल में भेजा गया। 17 फरवरी, 1883 को कालापानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर (अदन, यमन) ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया। साल 1984 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी की। दक्षिण मुंबई में उनकी एक मूर्ति की स्थापना भी की गयी।

स्रोत्र-हेरिटेज टाइम 17 फरवरी 2019

संकलन हसरत अली
शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश

सूर्या की 3 फिल्मों को नाजरिया नाजिम ने कर दिया था रिजेक्ट, चौथी बार में बनी बात, एक्टर ने की जमकर तारीफ





सूर्या ने खुलासा किया कि नाजरिया नाजिम ने उनकी तीन फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे। चौथी बार में दोनों की जोड़ी बनी। फिल्म 'सीन' 6 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। सूर्या ने खुलासा किया कि नाजरिया नाजिम ने उनकी तीन फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे। चौथी बार ऑफर मिलने पर नाजरिया ने सूर्या के साथ काम करने के लिए हामी भरी। सूर्या ने नाजरिया के आत्मविश्वास और करियर को लेकर उनकी स्पष्ट सोच की तारीफ की। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'सीन' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री नाजरिया नाजिम नजर आने वाली हैं। दोनों पहली बार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सूर्या ने नाजरिया को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है। सूर्या ने बताया कि वह काफी समय से नाजरिया के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने उनकी तीन फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे। आखिरकार चौथी बार में दोनों साथ काम करने के लिए तैयार हुए। हैदराबाद में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान सूर्या ने बताया कि वह हमेशा से नाजरिया नाजिम के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते थे। सूर्या की तीन फिल्मों को नाजरिया ने किया था मना अभिनेता सूर्या ने कहा कि इससे पहले भी तीन फिल्मों के लिए एक्ट्रेस से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने हर बार ऑफर ठुकरा दिया। चौथी कोशिश में नाजरिया ने फिल्म के लिए हामी भरी। सूर्या ने नाजरिया के फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और अभिनय के प्रति नजरिए का सम्मान करते हैं। अभिनेता के मुताबिक, नाजरिया ने पिछले करीब 12 सालों में तमिल फिल्मों के कई ऑफर भी ठुकराए हैं। सीन को बताया मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सूर्या ने फिल्म की कहानी और अपनी टीम के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि 'सीन' एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसमें कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म में कई प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ नए चेहरे भी नजर आएंगे। अभिनेता ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म में कोई एक शख्स नहीं, बल्कि सभी मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। अभिनेता ने पूरी टीम को एक परिवार बताया और कहा कि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सूर्या ने यह भी बताया कि इस साल यह उनका तीसरा प्रमोशनल इवेंट है और वह इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी करेंगी नाजरिया नाजिम की बात करें तो वह करीब 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रही हैं। शादी के बाद उन्होंने तमिल फिल्मों से दूरी बना ली थी और मलयालम प्रोजेक्ट्स में काम करती रहीं। अब 'सीन' के जरिए वह एक बार फिर तमिल दर्शकों के बीच आने वाली हैं। फिल्म में नाजरिया और सूर्या के अलावा नस्लेन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

इमरान हाशमी ने पकड़ी हॉरर की राह, 'राज' के बार पर्दे पर दिखेगा 'रूह' का खौफ



इमरान हाशमी जल्द ही हॉरर-म्यूजिकल फिल्म 'रूह' में नजर आएंगे। मयंक शर्मा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। इमरान हाशमी जल्द ही टिप्स फिल्म्स की हॉरर-म्यूजिकल फिल्म 'रूह' में नजर आएंगे। फिल्म में हॉरर, रोमांस और संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। इमरान हाशमी की फिल्म 'रूह' साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी एक बार फिर दर्शकों को डराने और रोमांचित करने की तैयारी में हैं। अपनी आगामी फिल्म 'गनमास्टर G9' को लेकर चर्चा में चल रहे अभिनेता के खाते में एक और बड़ा प्रोजेक्ट जुड़ गया है। इमरान जल्द ही हॉरर-म्यूजिकल फिल्म 'रूह' में नजर आएंगे। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें डर और रोमांस के साथ संगीत का भी जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को लेकर भी जानकारी शेयर कर दी है।

Jackie Shroff की फिल्म काली खेती का टीजर आया सामने, 20 नवंबर को लॉन्च होगी ये हॉरर फिल्म



जैकी श्रॉफ की फिल्म 'काली खेती' का टीजर रिलीज हो गया है। ग्रामीण लोककथाओं, रहस्यमयी शक्तियों और पुश्तैनी अभिशापों पर आधारित यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। जैकी श्रॉफ की हॉरर फिल्म काली खेती का टीजर रिलीज खून पीने वाले खेत और पुश्तैनी अभिशाप की दिखी कहानी 20 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म, सनी देओल की 'सूर्या' से टक्कर 90 के दशक के सुपरस्टार और बॉलीवुड में जग्गू दादा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ जेलर 2 में काम कर चुके जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म का टीजर सामने आ गया है। 3 नवंबर 2026 को आधिकारित तौर पर फिल्म काली खेती का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये एक सुपरनेचुरल रूरल थ्रिलर फिल्म है, जो इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म की कहानी ग्रामीण लोककथाओं, पुरानी मान्यताओं और पुश्तैनी अभिशापों के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जै कब रिलीज होगी फिल्म जैकी श्रॉफ की ये हॉरर फिल्म पहले 23 अक्टूबर को रिलीज की जाने वाली थी, हालांकि कुछ कारणों से मेकर्स ने इसे टालकर अब 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है। इस फिल्म की सीधी टक्कर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म सूर्याः अंत से आरंभ से हो सकती है। आखिरी बार इस फिल्म में नजर आएं थे जैकी श्रॉफ बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ आखिरी बार सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई हासिल की है। इससे पहले जग्गू दादा साल 2026 में फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। ये फिल्म 29 मई 2026 को रिलीज हो चुकी है। की श्रॉफ निभाएंगे मुख्य भूमिका काली खेती फिल्म की कहानी ग्रामीण लोककथाओं, पुरानी मान्यताओं और पुश्तैनी अभिशापों के इर्द-गिर्द बुनी हुई है। जैकी श्रॉफ की इस फिल्म के टीजर में एक ऐसे डरावने गाँव को दिखाया गया है जहाँ रात के अंधेरे में रहस्यमयी शक्तियां जागती हैं और वहाँ के खेत लोगों का खून पीने लगते हैं। इसी शैतानी ताकत की सच्चाई का पता लगाने का ज़िम्मा जैकी श्रॉफ का किरदार उठाता है। जैकी श्रॉफ के साथ नजर आएंगे ये कलाकार फिल्म काली खेती में जैकी श्रॉफ के साथ शरद केलकर भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इन दो दिग्गज कलाकारों के साथ ही इस फिल्म में मिर्जापुर फेम एक्ट्रेस नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी भी महत्वपूर्ण किरदारों में हैं।

ऋषभ पंत फिटनेस टेस्ट में फेल, न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारत को बड़ा झटका; अब 48 घंटे में होगा दूसरा टेस्ट



ऋषभ पंत न्यूजीलैंड दौरे से पहले बेंगलुरु के COE में फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। जानिए साइड स्ट्रेन से जूझ रहे पंत के पास फिटनेस साबित करने का दूसरा मौका क्या है। ऋषभ पंत पहला फिटनेस टेस्ट पास करने में असफल रहे। ईरानी कप के दौरान लगी पसलियों की चोट (साइड स्ट्रेन) के कारण वह टेस्ट फेल हुए। अगले 48 घंटों में होने वाला दूसरा टेस्ट तय करेगा कि वह न्यूजीलैंड जाएंगे या नहीं। न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपना पहला फिटनेस टेस्ट पास करने में असफल रहे हैं।

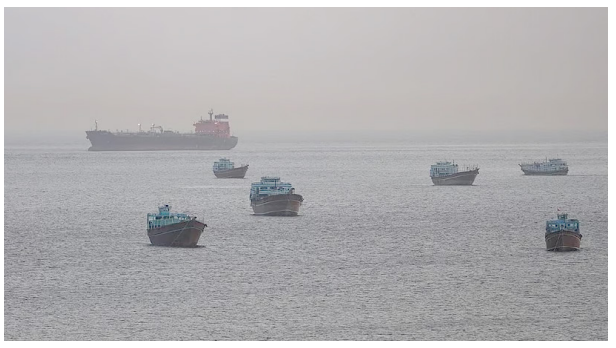
हार्दिक पांड्या छोड़ेंगे मुंबई इंडियंस का साथ? पंजाब किंग्स में ट्रेड होने की बड़ी खबर, अर्शदीप सिंह जाएंगे MI!



मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी करने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आगामी सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) की जर्सी में नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर बातचीत जारी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या IPL 2027 के आगामी सीजन में पंजाब किंग्स में जा सकते है। खिलाड़ियों की अदला-बदली पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स ट्रेड विंडो के जरिए हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में करेगी शामिल IPL 2027 के 20वें सीजन के आगाज होने से पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी करने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आगामी सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) की जर्सी में नजर आ सकते हैं। दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़े 'ट्रेड' यानी खिलाड़ियों की अदला-बदली पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स में जाएंगे पांड्या? दरअसल, स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स (PBKS) ट्रेड विंडो के जरिए हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच गई है। मुख्य कोच रिकी पोंटिंग की देखरेख में पंजाब फ्रेंचाइजी की मुंबई इंडियंस (MI) के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। इस मेगा ट्रेड डील के तहत, भारतीय स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद के मुंबई इंडियंस (MI) में जाने की पूरी संभावना है। अगर यह डील फाइनल होती है, तो अर्शदीप सिंह आईपीएल इतिहास में पहली बार पंजाब किंग्स के अलावा किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। MI ने 3 अन्य फ्रेंचाइजी से भी की थी बात बता दें कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए मुंबई इंडियंस ने केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि कम से कम 3 अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ भी संभावनाएं तलाशी थीं।

फिर कमर्शियल जहाज पर निशाना! भारतीय नाविक की मौत पर भारत ने जताई चिंता, तनाव तुरंत कम करने का आह्वान किया

विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले को लेकर बयान जारी किया है। बयान में MSV अल जुसुफी पर हुए हमले की निंदा की गई है। इस घटना में एक भारतीय की मौत हो गई। ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया हमले में भारतीय नाविक की मौत पर भारत का बयान घटना को लेकर भारत ने चिंता व्यक्त की है ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत होगई। भारत ने मंगलवार को पश्चिम एशिया में तनाव को तुरंत कम करने और राजनयिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में, भारत ने सोमवार शाम ओमान के लिमाह के पास भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज 'MSV अल जुसुफी' पर हुए हमले की निंदा की। इस घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोगों को बचा लिया गया। स्थिति पर भारत की नजर विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा



है, ताकि बचाए गए भारतीय नागरिकों और मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। बयान में कहा गया कि हम कल शाम ओमान के लिमाह के पास एक कमर्शियल जहाज 'MSV अल जुसुफी' पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 14 भारतीय नागरिकों में से 13 को बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की चोट लगने के कारण दुखद मौत हो गई। तनाव कम करने की अपील भारत सरकार भारतीय नागरिकों तथा मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर बार-बार हो रहे हमलों पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताते हुए तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान निकालने की भारत की मांग को दोहराया। कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक बताया है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता को बहाल करने की मांग की। ओमान कोस्ट गार्ड की मदद से रेस्क्यू यह बयान तब आया है जब केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओमान के तट के पास 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले जहाज पर हुए हमले के बाद एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर को ओमान के तट के पास से गुजरते समय जहाज से एक अज्ञात हवाई वस्तु टकरा गई। ओमान कोस्ट गार्ड ने 13 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बचा लिया। मृतक नाविक की पहचान गुजरात के गंधार नाहिम अजीज के रूप में हुई है।

मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी हारी तो क्या जाएगी राष्ट्रपति की कुर्सी? भारतीय मूल के वोटर्स क्यों हैं अहम



मिडटर्म चुनाव से ट्रंप की राजनीतिक ताकत की परीक्षा होगी। जानिए रिपब्लिकन पार्टी की हार का राष्ट्रपति के कार्यकाल, महाभियोग और भारतीय मूल के वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा। मिडटर्म चुनाव में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की सीटों के लिए मतदान होता है रिपब्लिकन पार्टी की हार से ट्रंप को कानून और बजट पास कराने में मुश्किलें आ सकती हैं भारतीय मूल के वोटर्स करीबी मुकाबले वाले राज्यों में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं अमेरिका में मिडटर्म चुनाव की उल्टी गिनती खत्म हो चुकी है और आज जनता अपने वोट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले दो साल की राजनीतिक राह तय करेगी। यह चुनाव सिर्फ संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की ताकत का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ट्रंप की नीतियों और फैसलों पर भी असर डालेगा। ऐसे में सवाल आता है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अगर बहुमत गंवा देती है, तो क्या राष्ट्रपति के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या ट्रंप को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? और इन चुनावों में भारतीय मूल के वोटर्स की भूमिका कितनी अहम होगी? मिडटर्म चुनाव क्या होते हैं? अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक दो साल बाद होने वाले चुनाव को मिडटर्म चुनाव कहा जाता है। इन चुनावों में अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की सीटों के लिए मतदान होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर चुनाव होता है जबकि सीनेट की 100 सीटों में से लगभग एक तिहाई सीटों पर मतदान कराया जाता है। 2026 में मिडटर्म चुनाव 3 नवंबर को होने हैं। इन चुनावों के जरिए अमेरिकी जनता यह तय करती है कि कांग्रेस में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा। ट्रंप की पार्टी हार गई तो क्या होगा? अगर रिपब्लिकन पार्टी मिडटर्म चुनाव में बहुमत गंवा देती है तो ट्रंप के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। सबसे बड़ा असर कानून बनाने की प्रक्रिया पर पड़ेगा।

रूस और यूक्रेन के एयर रेड अलर्ट सिस्टम पर साइबर हमला, लोगों को मिले परमाणु हमले के फर्जी संदेश

रूस और यूक्रेन के एयर रेड अलर्ट सिस्टम पर साइबर हमला हुआ। लोगों को परमाणु, रासायनिक हमले और गोलीबारी की फर्जी चेतावनियां मिलीं, जिससे अफरातफरी मच गई। यूक्रेन के अलर्ट सिस्टम में परमाणु और रासायनिक हमले के फर्जी संदेश भेजे गए। रूस में भी परमाणु हमले की झूठी चेतावनी देकर लोगों में दहशत फैलाई गई। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर साइबर हमले के आरोप लगाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब साइबर हमलों के नए मोर्चे तक पहुंच गया है। रविवार (1 नवंबर) को पहले यूक्रेन के एयर रेड अलर्ट सिस्टम को हैक कर लिया गया। इसके बाद देशभर में सायरन बजने लगे और लोगों के मोबाइल पर परमाणु हमले, रासायनिक हमले और सड़कों पर गोलीबारी होने की फर्जी चेतावनियां भेजी गईं। कुछ घंटे बाद रूस के आपातकालीन अलर्ट सिस्टम पर भी साइबर हमला हुआ।



वहां भी लोगों को परमाणु हमले से जुड़े फर्जी संदेश मिले। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर साइबर हमले के आरोप लगाए हैं। यूक्रेन में रेडिएशन और केमिकल हमले की चेतावनी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन में फर्जी अलर्ट रात करीब 10:47 बजे शुरू हुए। सबसे पहले राजधानी कीव में रेडिएशन खतरे का संदेश भेजा गया। इसमें कहा गया कि शहर में विकिरण का खतरा घोषित कर दिया गया है। इसके करीब एक मिनट बाद रूसी भाषा में दूसरा संदेश आया। इसमें लिखा था कि पूरे यूक्रेन में परमाणु हमले का अलर्ट जारी होगा और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस की ओरेशनिक मिसाइल आ रही है। इसके बाद रासायनिक हमले और कीव की सड़कों पर गोलीबारी होने की चेतावनी दी गई। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी गई। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने स्पष्ट किया कि देश में रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है।

WMO की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने की भारत की तारीफ, साइक्लोन मैनेजमेंट में बताया रोल मॉडल



एंड्रिया सेलेस्टे साउलो ने आपदा प्रबंधन के लिए भारत की तारीफ की है। उन्होंने दूसरे देशों के लिए रोड मॉडल बताया है। साइक्लोन अर्नब के बाद मुरासु की तैयारी को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। WMO की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने की भारत की तारीफ की है आपदा प्रबंधन के लिए सराहा और दुसरे देशों के लिए रोल मॉडल कहा अर्नब तूफान के बार मुरासु की तैयारी के लिए भारत की तारीफ की विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने भारतीय मौसम विभाग और जमीन पर काम कर रहे आपदा प्रबंधन कर्मियों की रणनीति को सराहा है।

नेपाल में हवा में टकराए दो हेलीकॉप्टर, विदेशी नागरिक की मौत, हादसे का वीडियो वायरल

नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। हादसे में एक विदेशी नागरिक की मौत हुई, जबकि एक यात्री घायल हो गया। नेपाल के सोलुखुम्बु में सुबह 8:11 बजे दो हेलीकॉप्टरों की हवा में टक्कर हुई। हादसे में एक विदेशी नागरिक की मौत, जबकि एक यात्री घायल हुआ। घायल को प्रभु एयर के हेलीकॉप्टर से लुक्ला पहुंचाया गया। नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। यहां लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री घायल हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।



घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों हेलीकॉप्टर एयर डायनेस्टी और फिशटेल एयर के थे। ये मंगलवार सुबह करीब 8:11 बजे सोलुखुम्बु जिले के फेरीचे इलाके में एक-दूसरे से टकरा गए। हादसा काठमांडू से करीब 250 किलोमीटर दूर एक हेलीपोर्ट के पास हुआ। मृत विदेशी नागरिक की पहचान नहीं हुई जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर मौसम तमांग ने बताया कि हादसे में एक विदेशी नागरिक की मौत हुई है। हालांकि, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। दुर्घटना में एक अन्य यात्री भी घायल हुआ है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए प्रभु एयर के हेलीकॉप्टर से लुक्ला पहुंचाया गया। हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस फिलहाल घायल यात्री की स्थिति और दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार अन्य यात्रियों तथा क्रू मेंबर्स की संख्या को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, नवभारत इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य जानकारियां सामने आ सकती हैं।

3 नवंबर जन्म दिवस पर विशेष।

स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा

सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर सन् 1900 ई. को एक संपन्न ब्राह्मण परिवार मे हुआ था। इनके पिता अखेराज गोपा महारावल के दरबार मे उच्च पद पर आसीन थे। जैसलमेर मे रावल के अत्याचारो का भारी आतंक था। फिर भी कुछ युवको ने वहा जागृति की लहर फैलाने का अथक् प्रयास किया। इनमे सागरमल गोपा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपको जैसलमेर मे गुण्डाराज नामक पुस्तक लिखने के आरोप मे 25 मई सन् 1945 ई. को ही जेल मे डाल दिया गया। और वहा अनेक नारकीय यातनाएं दी जाने लगी। मारवाड लोक



परिषद के अध्यक्ष जयनारायण व्यास ने इसके लिए पोलिटिकल एजेन्ट को एक कडा विरोध पत्र भेजा ,परन्तु इससे पहले ही पुलिस ने उन पर तेल छिडक कर आग लगा दी ,परन्तु शहर मे पुलिश ने यह अफवाह फैला दी कि गोपा ने स्वंय तेल छिडककर आत्माहत्या का प्रयास किया है । इस पर सारा शहर उन्हे देखने के लिए उमड पडा ,परन्तु किसी को भी नही मिलने दिया। आपके इलाज का भी कोई प्रबन्ध नही किया गया । इस वेदना की हालत मे ही गोपाजी ने 4 अप्रैल सन् 1946 ई. को अपने प्राण त्याग दिए। सारा शहर ' सागरमल गोपा जिंदाबाद ' के नारो से गूंज उठा।पण्डित नेहरु ने गोपा जी की मृत्यु को एक जघन्य काण्ड बताते हुए कहा " इसे आत्माहत्या कहना एक शरारत है। यह एक ऐसी बात है ,जो केवल जैसलमेर के लिए ही नही वरन् दूसरे राजाओ के लिए भी शर्म की बात है।" स्वतंत्रता व मानवाधिकारो के लिए गोपा जी का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम मे स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। ऐसे बलिदानो से ही रियासतो के शर्मनाक शासन का पर्दाफाश हुआ।

संदर्भ-स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास
लेखक-गोवर्धनलाल पुरोहित
पृष्ट संख्या 425,426
संकलन हसरत अली
शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश

काजी तौकीर को मिला परिवार का प्यार, माही हुईं इमोशनल

'बिग बॉस 20' में फैमिली मैसेज सुनकर काजी तौकीर इमोशनल हो गए। वहीं, लव की मां की बातों से आहत माही रो पड़ीं और शो छोड़ने का फैसला करती नजर आईं। का 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्तों, बहस और इमोशनल ड्रामे का सिलसिला जारी है। हालिया एपिसोड में जहां अरिशफा की पढ़ाई और हाइट को लेकर विवाद देखने को मिला, वहीं फैमिली मैसेज ने घरवालों को भावुक कर दिया। काजी तौकीर अपने परिवार का संदेश सुनकर इमोशनल हो गए। दूसरी ओर, माही को लव की मां का मैसेज सुनकर काफी बुरा लगा। वह



रोती नजर आईं और शो छोड़ने तक का फैसला कर लिया। एपिसोड की शुरुआत यंग के अरिशफा की पढ़ाई पर टिप्पणी करने से हुई। इसके बाद स्काउट ने भी अरिशफा की हाइट का मजाक उड़ाया। दोनों की बातें सुनकर अरिशफा नाराज हो गईं और उनकी यंग व स्काउट के साथ तीखी बहस हो गई। घर का माहौल उस वक्त काफी तनावपूर्ण हो गया। इस विवाद के बाद स्काउट, यंग और आम्रपाली ने आपस में फैसला किया कि वे अब अरिशफा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आम्रपाली पर टिप्पणी को लेकर काजी और यंग भिड़े घर में एक और बहस तब शुरू हुई, जब यंग ने काजी तौकीर को आम्रपाली के बारे में विवादित टिप्पणी करने से रोका। उन्होंने काजी से कहा कि उन्हें आम्रपाली पर बच्चे बेचने जैसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यंग की इस बात पर काजी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और दोनों के बीच बहस छिड़ गई। इस मुद्दे ने घर के माहौल को और गरमा दिया। जी तौकीर अपनी फैमिली का मैसेज सुनकर इमोशनल हो गए।

दीया मिर्जा विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट

सोशल मीडिया अकाउंट्स से दीया मिर्जा का यह वीडियो हटा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के इस कदम पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियां बेहद चिंताजनक हैं और प्रशासनिक संस्थाओं को राजनीतिक दबाव में आकर जनहित के कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है: बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को कड़ा संदेश देते हुए याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां कानून और जनस्वास्थ्य सर्वोपरि हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जब कोई फैसला या अभियान सार्वजनिक हित और अदालती आदेशों के पालन के लिए चलाया जाता है, तो उसे राजनीतिक विवादों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब BMC को यह वीडियो फिर से बहाल करना होगा।

महाराष्ट्र सरकार 23 नवंबर को

के वित्त विभाग ने खुले बाजार से जुटाए गए 6.82% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 2026 के मोचन (Redemption) और बकाये के भुगतान की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज्य सरकार इस ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान 23 नवंबर 2026 को करेगी। इसके साथ ही 22 नवंबर 2026 तक का देय ब्याज भी निवेशकों को चुका दिया जाएगा। छुट्टी होने पर क्या होगा? यदि महाराष्ट्र सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत इस तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है, तो ऋण का भुगतान राज्य के संबंधित कार्यालय द्वारा उससे ठीक पहले वाले वर्किंग डे पर किया जाएगा। 23 नवंबर 2026 से इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और न ही कोई ब्याज देय होगा। भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, 2007 के उप-नियम 24(2) और 24(3) के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों के रिडेम्पशन से प्राप्त राशि, पंजीकृत धारक के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर दी जाएगी। इसके लिए मूल ग्राहक या बाद के धारक को अपने बैंक खाते का विवरण संबंधित बैंक, ट्रेजरी, सब-ट्रेजरी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी सहायक कंपनियों की उस शाखा में जमा करना होगा, जहां सिक्यूरिटी पंजीकृत हैं या जहां ब्याज का भुगतान जमा किया जाना है। भौतिक बॉन्ड धारकों के लिए निर्देश यदि बैंक खाते का विवरण या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो 6.82% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2026 के धारकों को भुगतान की तारीख पर प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी करने के लिए, कम से कम 20 दिन पहले अपनी प्रतिभूतियां 'पब्लिक डेट ऑफिस' में जमा करनी होगी। सिक्यूरिटीज को मोचन (रिडेम्पशन) के लिए जमा करते समय, उनके पीछे की तरफ एक एंडोर्समेंट करना होगा, जिसमें प्रमाणपत्र पर उल्लिखित मूल राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई हो। विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि प्रतिभूतियां प्रमाणपत्रों के रूप में हैं, तो उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके सहयोगी बैंकों की उस शाखा में जमा किया जाना चाहिए जो ट्रेजरी कार्यों को संभालती है। इन्हें सीधे किसी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी कार्यालय में जमा नहीं किया जाना चाहिए। अन्य स्थान पर भुगतान प्राप्त करने का नियम जो बॉन्ड-धारक भुगतान उस जगह के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं जो मूल रूप से फंड के वितरण के लिए तय की गई थी, उन्हें अपने बॉन्ड (सभी जरूरी औपचारिकताओं के साथ) रजिस्टर्ड और बीमित डाक के जरिए संबंधित 'पब्लिक डेट ऑफिस' को भेजने चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि पब्लिक डेट ऑफिस डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान के किसी अन्य साधन के जरिए भुगतान की सुविधा देगा। यह डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसके सहयोगी बैंकों की किसी भी ऐसी शाखा में भुनाया जा सकेगा, जो महाराष्ट्र राज्य के भीतर सरकारी ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी के रूप में काम करती है।

महाराष्ट्र में FDA की बड़ी

अभियान चलाया। इस दौरान 9 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। जब्त सामान में पतंजलि ब्रांड का गाय का घी भी शामिल है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सभी सात प्रशासनिक विभागों में 114 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। नियमों और साफ-सफाई में गंभीर कमियां मिलने पर 19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित किए गए। छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि घी जब्त अभियान के तहत एफडीए ने छत्रपति संभाजीनगर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से करीब 20 लाख रुपये मूल्य का 2,279 लीटर पतंजलि गाय का घी जब्त किया। अधिकारियों के मुताबिक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत गलत लेबलिंग और मिलावट के संदेह में यह कार्रवाई की गई। हालांकि, जब्ती अपने आप में मिलावट साबित नहीं करती। उत्पाद की जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। भिवंडी में 1.44 लाख किलो से अधिक खाद्य तेल जब्त रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे बड़ी जब्ती कोंकण विभाग में हुई। ठाणे जिले के भिवंडी में एक स्थान से विभिन्न ब्रांडों का 1.44 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्य तेल जब्त किया गया। इसके अलावा पुणे, सतारा, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर में भी कार्रवाई की गई। इन जगहों से खाद्य तेल, चावल, दाल और गुड़ सहित कई उत्पाद जब्त किए गए। एफडीए के अभियान में मसाले, आटा, डेयरी उत्पाद, मिठाइयां, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और बेकरी के सामान की भी जांच की गई। मुंबई में निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में गंदगी, कीड़े-मकोड़े, जरूरी दस्तावेजों की कमी और खाद्य पदार्थों के भंडारण में लापरवाही जैसी खामियां पाई गईं। अलग अभियान में 79.4 लाख का सामान जब्त 28 से 31 अक्टूबर के बीच प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए गए एक अलग अभियान में एफडीए ने 17 प्रतिष्ठानों से 79.4 लाख रुपये का सामान जब्त किया। इस कार्रवाई में 13 एफआईआर दर्ज की गईं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया और छह वाहन जब्त किए गए। उपभोक्ताओं को एफडीए की सलाह त्योहारी सीजन में एफडीए ने लोगों से केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खाद्य उत्पाद खरीदने की अपील की है। विभाग ने बिना लेबल वाले या खुले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी है। खरीदारी करते समय पैकेट पर दर्ज सामग्री, बैच नंबर, पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख जरूर जांचें। किसी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग को शिकायत करें।

पृष्ठ 1/8 का शेष

ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से कुचलने

पुलिस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस इस वीडियो और शिकायत में दर्ज आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इसी बीच पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र भेजकर जूही मेहता का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। अब परिवहन विभाग इस सिफारिश पर क्या निर्णय लेता है, इस पर नजर रहेगी। मामले में पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिवाली की ऑनलाइन शॉपिंग

बीच, साइबर ठग भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। वे फेक लिंक्स, लुभावने विज्ञापनों और फर्जी कॉल्स के जरिए मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए घात बिछाए बैठे हैं। इस बढ़ते खतरे को भांपते हुए मुंबई महाराष्ट्र साइबर सेल ने कमर कस ली है। पुलिस ने लोगों को सतर्क करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। साथ ही, बैंक खातों से गाढ़ी कमाई उड़ने से रोकने के लिए कई एहतियाती उपाय भी साझा किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में थोड़ी सी सावधानी और सजगता ही ऑनलाइन फ्रॉड के जाल से सुरक्षित रख सकती है। जरूरी बातें जो फेस्टिवल को बनाएंगी और भी सुरक्षित साइबर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अविश्वसनीय रूप से अच्छे ऑफर्स के साथ कॉल करने वाले अजनबियों से बात न करें। आमतौर पर ऐसे ऑफर नकली होते हैं। फोन, एसएमएस, सोशल मीडिया या ईमेल पर भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी हालत में अपना यूजरनेम, पासवर्ड और ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को न बताएं, किसी भी शॉपिंग कंपनी का लिंक खोजने के लिए सीधे गूगल सर्च पर न जाएँ। सर्च में टॉप पर आने वाला परिणाम नकली हो सकता है और असली ब्रांड का मुखौटा लगाकर आ सकता है। हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। साइट रिव्यू चेक कर करें खरीदारी पुलिस एक वरिष्ठ साइबर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमेशा साइट रिव्यू चेक करके ही खरीदारी करें। त्योहारों के दिनों में लोग सोना, चांदी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ऑनलाइन खरीदारी बड़े पैमाने पर करते हैं। शॉपिंग करने से पहले साइट की प्रमाणिकता जांच लें और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही पेमेंट करें। फिर भी अगर आप ठगी के शिकार होते हैं, तो बिना देर किए नजदीकी पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाएं। इसके अलावा तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आपके खाते से निकले पैसे को समय रहते फ्रीज किया जा सके। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रखें इन बातों का ध्यान भरोसेमंद और जानी-मानी वेबसाइटों से ही शॉपिंग करें, फेक वेबसाइट और एप से हमेशा सावधान रहें। अगर कोई डील जरूरत से ज्यादा आकर्षक लग रही है, तो सतर्क हो जाएं क्योंकि यह साइबर ठगों का मायाजाल हो सकता है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट में करने से पहले वेबसाइट की सुरक्षा जांच लें। खरीदारी करने से पहले उत्पाद और प्लेटफॉर्म का रिव्यू जरूर देखें कि पहले किसी अन्य ग्राहक ने वहां से खरीदारी की है या नहीं। किसी के साथ भी अपना ओटीपी शेयर न करें, किसी भी कॉलर के बहकावे में न आएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। दिवाली के ऑफर्स का इंतजार पूरा साल रहता है। डिस्काउंट और गिफ्ट के समय ऑनलाइन शॉपिंग का मजा ही कुछ और है, लेकिन साइबर ठगों ने त्यौहार की खुशियों को फीका कर दिया है। अब तो ऑनलाइन खरीदारी करने से भी डर लगने लगा है। अनीता राज विश्वकर्मा, सिलाई क्लास टीचर कई वर्षों से दिवाली के समय 66 आने वाले ऑफर्स पर महिलाएं खरीदारी करती थीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं बढ़ने के बाद। अब स्थानीय दुकानों पर जाकर खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। मुंबई पुलिस ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन इनसे और सख्ती से निपटने की जरूरत है।

महालक्ष्मी रेसकोर्स में पेड़ों के

क्लब परिसर में प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ बीएमसी के जी-दक्षिण विभाग ने यह कदम उठाया है। वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति के नियमों का उल्लंघन होने के बाद यह नोटिस जारी हुआ है, जिससे रेसकोर्स का विवाद गहरा गया है। बीएमसी के वृक्ष प्राधिकरण ने 28 नवंबर 2025 को आरडब्ल्यूआईटीसी को पेड़ों की कटाई और पुनर्रोपण की अनुमति दी थी। इसके तहत परिसर में मौजूद 13 पेड़ों को काटने, 12 पेड़ों का पुनर्रोपण करने और 43 पेड़ों को सुरक्षित रखने की शर्त थी। लेकिन 11 अगस्त 2026 को बीएमसी के अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान 43 सुरक्षित पेड़ों में से आठ पेड़ गायब मिले। इसके अलावा, पुनर्रोपण के मंजूर 12 पेड़ों में से 2 पेड़ भी मौके पर नहीं पाए गए। सहायक उद्यान अधीक्षक ने दर्ज कराई एफआईआर अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाए गए हैं।

इस मामले में सहायक उद्यान अधीक्षक ने 30 सितंबर 2026 को ताड़देव पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इससे पहले 21 अगस्त 2026 को एनसीआर दर्ज किया गया था।

बीएमसी महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है।

जी-दक्षिण विभाग के नामित अधिकारी ने 29 अक्टूबर 2026 को निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी किया है। निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित पक्ष को 24 घंटे के भीतर मंजूर अनुमति दिखाने का निर्देश दिया गया है। अनुमति न मिलने पर निर्माण सामग्री और मशीनरी हटाने की चेतावनी दी गई है। बन रहे आलीशान क्लब हाउस और बैंक्वेट हॉल प्रस्तावित योजना के अनुसार, इस ऐतिहासिक रेसकोर्स परिसर में कई आधुनिक सुविधाओं का प्रस्ताव है।

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई
CITY NEWS MUMBAI
बुधवार , 04 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

भिवंडी में मेट्रो दौड़ी, दिसंबर में सेवा शुरू होने की उम्मीद

कपूरबावड़ी से धामणकर नाका तक 13.5 किमी मार्ग पर ट्रायल रन सफल; सात स्टेशनों से जुड़ेगा शहर

अधिकारियों ने मेट्रो में सफर कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा, जाम से राहत की उम्मीद के बीच 2 हजार से अधिक संपत्तियों पर विस्थापन का खतरा

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडीः शहरवासियों का मेट्रो में सफर करने का सपना अब साकार होने के करीब पहुंच गया है। मेट्रो-5 परियोजना के तहत मंगलवार को कपूरबावड़ी से धामणकर नाका तक करीब 13.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल रन पूरा किया गया। इस दौरान परियोजना के अधिकारियों ने ट्रेन में सफर कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने दिसंबर 2026 तक मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई है। मेट्रो शुरू होने से भिवंडीकरों को सड़क यातायात और जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। कपूरबावड़ी से धामणकर नाका के बीच मेट्रो के सात स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें कपूरबावड़ी, बालकुम, काशेली, काल्हेर, पूर्णा, अंजुरफाटा और धामणकर नाका शामिल हैं। छह कोच वाली इस मेट्रो ट्रेन में प्रत्येक कोच में लगभग 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस तरह एक ट्रेन में करीब 300 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन की लंबाई लगभग 136 से 138 मीटर बताई गई है। ठाणे से शुरू होने वाला मेट्रो-5 मार्ग भिवंडी होते हुए कल्याण तक जाएगा। इस परियोजना से भिवंडी के नागरिकों को यातायात जाम से राहत मिलने के साथ ठाणे और कल्याण की ओर आवागमन भी अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। फिलहाल काशेली, पूर्णा, काल्हेर से धामणकर नाका तक मेट्रो निर्माण का काम तेजी से जारी है। मेट्रो परियोजना शहर के विकास और बेहतर परिवहन की उम्मीद जगा रही है, लेकिन इसके निर्माण से प्रभावित होने वाले संपत्ति धारकों की चिंता भी बढ़ गई है। अंजुरफाटा से धामणकर नाका, कल्याण नाका से टेमघर और साईंबाबा मार्ग से कोनगांव क्षेत्र तक प्रस्तावित मेट्रो मार्ग की चपेट में दो हजार से अधिक दुकानें और मकान आने की आशंका जताई जा रही है। इस परियोजना को लेकर करीब छह हजार नागरिकों ने मनपा प्रशासन के समक्ष शिकायतें और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। प्रभावित संपत्ति धारकों को आशंका है कि मेट्रो मार्ग के लिए निर्धारित सीमा में आने वाली उनकी संपत्तियों को तोड़ा जा सकता है। ऐसे में मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद के साथ प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास और उचित मुआवजे का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के चलते धामणकर नाका से कल्याण तक मेट्रो निर्माण कार्य फिलहाल रुका हुआ है।

ऐसे में मेट्रो के ट्रायल रन से जहां सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है, वहीं प्रभावित नागरिकों को राहत देने की चुनौती भी प्रशासन के सामने बनी हुई है।

दिवाली की ऑनलाइन शॉपिंग पर साइबर ठगों की नजर, मुंबई साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी



दिवाली शॉपिंग के दौरान साइबर ठगी से बचने के लिए मुंबई महाराष्ट्र साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। फर्जी लिंक्स और लुभावने ऑफर्स से रहें सावधान, ठगी होने पर 1930 पर करें कॉल। दिवाली पर ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साइबर ठगी का खतरा बढ़ा। फेक लिंक, कॉल और आकर्षक ऑफर्स से सावधान रहने की मुंबई साइबर सेल की अपील। ठगी होने पर तुरंत 1930 या cybercrime. gov.in पर शिकायत करें। दिवाली के अवसर पर ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज अपने चरम पर है। ग्राहक आकर्षक ऑफर्स और भारी छूट का लाभ उठाने के लिए बेताब रहते हैं। इस स्थिति को भुनाने के लिए जहां एक ओर ई-कॉमर्स कंपनियां तरह-तरह की लुभावनी डील्स पेश कर रही हैं, वहीं भीड़भाड़ से बचने और बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इस ...शेष 7 पर

भिवंडी के होटल में गाना बदलने पर खूनी संघर्ष, 11 गिरफ्तार

चॉपर से हमला, देसी पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप; दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

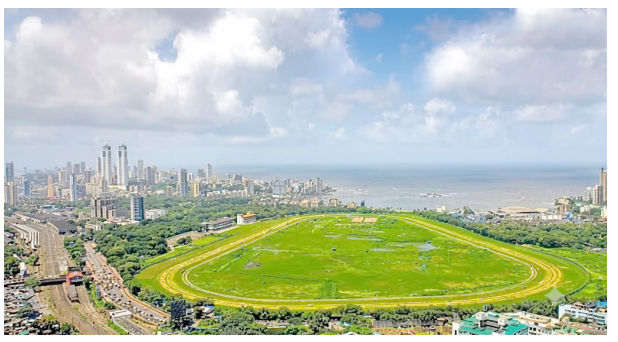
भिवंडीः भिवंडी तालुका के सोनाले स्थित नासिक-मुंबई हाईवे के तिशा होटल में गाना बदलने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। 1 नवंबर की रात हुई इस घटना में चॉपर से हमला करने और देसी पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप सामने आए हैं। झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए हैं। भिवंडी तालुका पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंदी गाना बजाने की मांग पर विवाद पुलिस के अनुसार, होटल में मराठी गाने बज रहे थे। इसी दौरान टावरीपाड़ा निवासी अनिकेत दत्तू जाधव (25) ने हिंदी गाना लगाने की मांग की। इस बात को लेकर नवनाथ आप्पा भोईर और उसके साथियों से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान चॉपर से हमला किया गया और देसी पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया। एक पक्ष के छह, दूसरे के पांच आरोपी गिरफ्तार अनिकेत जाधव की शिकायत पर पुलिस ने नवनाथ आप्पा भोईर (36), विशाल निरंकार गुप्ता (23), मयूर गोकुल म्हात्रे (20), करण कैलास पाटील (20), कुणाल परशुराम पाटील (22) और विनायक सुरेश म्हात्रे (44) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल चॉपर भी जब्त किया है। आरोपियों को 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वहीं, दूसरे पक्ष की शिकायत पर जयेश प्रकाश म्हात्रे, साईनाथ आप्पा पाटील, प्रशांत प्रभाकर वाघे, अनिकेत दत्तू जाधव और पंकज प्रेमदास गायकवाड को गिरफ्तार किया गया है। इस पक्ष ने भी मारपीट और देसी पिस्तौल के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। इन आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। भिवंडी तालुका पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। होटल में गाना बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद चॉपर और कथित पिस्तौल तक पहुंचने से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से कुचलने की कोशिश का आरोप, CEO जूही मेहता का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश



मुंबई के विले पार्ले में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से कुचलने की कोशिश के आरोप में घिरीं डिजिटल मीडिया कंपनी की जूही मेहता के खिलाफ पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। जूही मेहता का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश। विले पार्ले में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से कुचलने की कोशिश का आरोप। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। विले पार्ले में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ कथित बदसलूकी और उन्हें कार से कुचलने की कोशिश के मामले में डिजिटल मीडिया कंपनी की CEO जूही मेहता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। यह घटना 30 अक्टूबर की शाम संगीत महाभारत जंक्शन के पास हुई थी। कार की टक्कर के बाद लगा था ट्रैफिक जाम मिली जानकारी के अनुसार, जूही मेहता की महंगी कार की टक्कर एक अन्य वाहन से हो गई थी। इस हादसे के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। उस समय ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल प्रशांत हाके मौके पर पहुंचे। उन्होंने मेहता से कार हटाकर यातायात सुचारु करने को कहा। कांस्टेबल की ओर कार बढ़ाने का आरोप पुलिस शिकायत के अनुसार, कार हटाने को कहने पर जूही मेहता ने कांस्टेबल प्रशांत हाके के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की और बहस शुरू कर दी। आरोप है कि जब हाके ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी कार पुलिसकर्मी की दिशा में बढ़ा दी। हालात को भांपते हुए कांस्टेबल हाके समय रहते सड़क के किनारे हट गए। इससे वह कार की चपेट में आने से बच गए। इसके बाद आरोपी महिला कथित तौर पर तेज रफ्तार से जैवीपीडी जंक्शन की ओर निकल गईं। वीडियो के आधार पर जांच कर रही ...शेष 7 पर

महालक्ष्मी रेसकोर्स में पेड़ों के गायब होने पर BMC सख्त, निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी



बीएमसी ने महालक्ष्मी रेसकोर्स में प्रस्तावित निर्माण कार्य रोकने का नोटिस दिया। वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति का उल्लंघन कर 10 पेड़ गायब होने पर ताड़देव पुलिस में FIR दर्ज। महालक्ष्मी रेसकोर्स में पेड़ों के नियम उल्लंघन पर बीएमसी का नोटिस। निरीक्षण में 43 सुरक्षित पेड़ों में से 8 और 2 पुनर्रोपित पेड़ गायब मिले। बीएमसी ने निर्माण रोकने और 24 घंटे में अनुमति दिखाने का निर्देश दिया। महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कड़ी कार्रवाई की है। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्...शेष 7 पर

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486